

प्रश्नक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अंशभाग - 2

विषय: मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के ब्लॉक 'ए' एवं 4 न्यायालयों के ब्लॉक के बीच सीढ़ियों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वीकृति धनराशि को निरस्त किया जाना ।

महोदय,  
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 736/आठ/2007 बजट अंशभाग, दिनांक 2.3.07 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के ब्लॉक 'ए' एवं 4 न्यायालयों के ब्लॉक के बीच सीढ़ियों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में शासनादेश संख्या 21-टी(2)/XXXVI(1)/2006, दिनांक 12.10.06 द्वारा धनराशि रु० 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) स्वीकृत की गई थी । अब कार्य की आवश्यकता न होने के कारण उक्त शासनादेश को महानिबन्ध राज्यपाल निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

यदि उक्त शासनादेश दिनांक 12.10.2006 द्वारा स्वीकृत धनराशि को आहरित कर लिया गया हो, तो कृपया उसे कोषागार में जमा कर दिया जाय ।

यह आदेश विल अंशभाग-5 के अंशसंकीर्ण संख्या-124/XXVII(5)/2006, दिनांक 15.3.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं ।

भवदीय,

( आर०डी०पालीवाल )

सचिव ।

संख्या: 72-टी(2)/XXXVI(1)(2)/2006-21-टी(2)/06-तद्विनिक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, मजरा, देहरादून ।
2. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
7. नियोजन विभाग/विल अंशभाग-5/एन०आई०सी० ।
8. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गाईड बुक ।

आशा है,

( एम०एम०समवाल )

अनु सचिव ।